साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2015/72544

चौपाल से भोपाल तक

भोपाल, सोमवार, 9-15 दिसंबर 2024 वर्ष-10, अंक-34

भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, मुरैना, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठः-8,मूल्यः- 2 रुपए

सीएम डॉ. मोहन यादव केंद्रीय जलशक्ति मंत्री से बोले-बूंद-बूंद जल बचाने का अभियान प्रशंसनीय

'कर्मभूमि से जन्मभूमि' के तहत मप्र में होंगे 15 हजार बोर

भोपाल। जागत गांव हमार

पीएम नरेंद्र मोदी के जलसंचय संकल्प को जन-आंदोलन बनाने के क्रम में 'कर्मभूमि से जन्मभूमि' कार्यक्रम की परिकल्पना की गई है। इसमें गुजरात में रह रहे मध्यप्रदेश, राजस्थान और बिहार के व्यवसायी अपनी जन्म भूमि में जल संचय के उद्देश्य से बोर की व्यवस्था कर रहे हैं। इसमें राजस्थान में एक लाख 60 हजार और मध्यप्रदेश में 15 हजार बोर बनवाए जाने हैं। बिहार के 10 जिलों के हर गांव में 4 बोर बनवाए जाने का निर्णय लिया गया है। यह बात केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल ने नई दिल्ली में 'कर्मभूमि से जन्मभूमि' के प्रभावी क्रियान्वयन पर त्रिपक्षीय बैठक के दौरान कही। इस दौरान मध्यप्रदेश के सीएम डॉ. मोहन यादव और राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे।

सतना में शुरू हो गया योजना का काम वहीं मप्र के सीएम ने कहा कि वर्षा जल को संग्रहित कर भूगर्भ में जल भंडारण क्षमता के विकास के लिए चलाई जा रही 'कर्मभूमि से जन्मभूमि' योजना एक अभिनव पहल है। इस योजना में गुजरात में रहकर व्यापार करने वाले अन्य प्रदेशों के व्यापारियों द्वारा स्वयं के संसाधनों से अपने राज्यों में बोर लगवाने का काम किया जा रहा है। मध्यप्रदेश के सतना जिले में इस योजनान्तर्गत कार्य आरंभ हो गया है। योजना में पूरे प्रदेश में 15 हजार बोर लगाने का लक्ष्य है। शासकीय संसाधनों के बिना गुजरात व्यापार करने वाले व्यापारियों की भागीदारी से चल रहा बूंद-बूंद जल बचाने का यह अभियान प्रशंसनीय है।

बाधाओं पर चर्चा

सीएम डॉ. मोहन यादव ने योजना के संचालन के लिए बैठक में जिला कलेक्टर को नोडल अधिकारी नियुक्त करने, गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध तरीके से योजना को पूरा करने और इसके क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने के संबंध में विस्तृत चर्चा की।

राजस्थान होगा पानी-पानी

राजस्थान के सीएम शर्मा ने बताया कि पीएम की पहल पर सूरत के व्यापारियों द्वारा शुरू की गई यह योजना राजस्थान के सिरोही और जोधपुर जिलों में प्रारंभ हो चुकी हैं। राजस्थान राज्य में वाटर रिचार्ज में सहयोग के लिए यह योजना वरदान साबित होगी।

-मप्र के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना का अजीबोगरीब बयान,कहा

खाद की कमी मेरा विषय नहीं सहकारिता विभाग का काम

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश में जहां एक ओर किसान खाद के लिए परेशान हो रहे हैं। धरना-प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने यह कह कर चौंका दिया कि मप्र में खाद की कमी की समस्या मेरा विषय नहीं है। यही नहीं, मंत्री ने यह भी कहा कि खाद वितरण सहकारिता विभाग का काम है। कंषाना ने कहा कि प्रदेश में कहीं खाद की कमी नहीं है। यदि कहीं खाद की कमी है तो मुझे बताएं, मैं खाद पहुंचाऊंगा। मंत्री ने कहा कि कौन से जिले और कौनसी तहसील में खाद की जरूरत है। हालांकि, यह उर्वरक विभाग का मामला है। खाद का वितरण सहकारिता विभाग करता है। आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं आपको उसका उत्तर दे रहा हूं। वहीं खाद खरीदी केंद्रों पर लग रही किसानों की भीड़ पर कृषि मंत्री कंषाना ने तर्क दिया कि लोग खाद लेने जब जाते हैं तो एक दुकान पर नहीं मिलती तो दूसरी दुकान पर चले जाते हैं। बंटने में अगर थोड़ी कठिनाई आती है और 100-50 लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो वह उसको कहते हैं कि खाद नहीं मिल रहा।

पहले कहा था रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण खाद की कमी

- यदि कहीं खाद की कमी है तो मुझे बताएं,मैं खाद पहुंचाऊंगा
- **सच्चाईः** उर्वरक विभाग नाम का कोई विभाग मप्र में नहीं
- विपक्ष बोला-सीएम को ऐसे मंत्री से इस्तीफा ले लेना चाहिए
- डिमांड भेजने से खाद मंगाने तक कृषि विभाग का ही जिम्मा

सिंघार... विभाग नहीं पता तो पद छोड़ दो...

विस में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तंज कसते हुए कहा कि रामनिवास रावत तो अपने निवास चले गए, अब कंषाना को भी इस्तीफा दे देना चाहिए। सिंघार ने कहा कि कृषि मंत्री कंषाना को किसानों की समस्याओं का ही ज्ञान नहीं है। मुख्यमंत्री को ऐसे मंत्री से तत्काल इस्तीफा लेना चाहिए, जिसे अपने काम और जिम्मेदारी के बारे में नहीं पता है। खाद नहीं मिलने की शिकायतें हर जिले से आ रही हैं, मंत्री इसे नजरअंदाज कर रहे हैं। सरकार को बुलेटिन जारी कर स्थिति साफ करनी चाहिए।

सिस्टम पर एक नजर

हर साल सीजनवार पिछले साल की बोवनी और किसानों के ताजा रुझान के आधार पर खाद की जरूरत का आकलन करना कृषि विभाग का काम है। वही केंद्र को राज्य में खाद की डिमांड भेजता है। मंगवाता है। आवंटन के बाद जिलों में खाद भेजने व वितरण का जिम्मा मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) का है। यह सहकारिता विभाग के अधीन आता है। जबकि उर्वरक विभाग नाम का कोई विभाग प्रदेश में नहीं है।

किसान...खाद के लिए कतार में खाद संकट के कारण प्रदेशभर में खरीद केंद्रों पर करीब डेढ़ महीने से लग रही किसानों की कतारों को लेकर पूछे गए सवाल पर कृषि मंत्री ऐंदल सिंह कंषाना अपने गैर जिम्मेदाराना बयान पर घिर गए हैं। गौरतलब है कि प्रदेश में पिछले डेढ़ माह से पर्याप्त खाद न मिलने से किसान परेशान हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जब यूके-जर्मनी के दौरे से लौटे तो उसी रात उन्होंने खाद वितरण में हो रही परेशानी को लेकर अफसरों की बैठक ली थी। एक सच्चाई ये भी है कि मंत्री के गृह संभाग में सबसे ज्यादा कमी है।

अब मोहन सरकार ऑनलाइन करेगी निगरानी

मध्य प्रदेश में 45 लाख टन धान की होगी सरकारी खरीद

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्य प्रदेश में आज से न्यूनतम समर्थन मूल्य (2,300 रुपए प्रति क्विंटल) पर धान का उपार्जन 1,412 केंद्रों पर होगा। 45 लाख टन खरीदी का लक्ष्य रखा गया है। गुणवत्तायुक्त उपार्जन के लिए ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। किसान जो उपज लेकर आएगा, उसकी गुणवत्ता का आकलन नमी, कचरा और टूटन के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद ही उपज को स्वीकार या अस्वीकार कर पर्ची जारी की जाएगी। यदि उपज गुणवत्तायुक्त नहीं होगी तो उसे लौटाकर ठीक करके लाने के लिए कहा जाएगा। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सामान्य किस्म की धान 2,300 और ग्रेड ए धान का समर्थन मूल्य 2,320 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदी जाएगी। गुणवत्तायुक्त उपज का ही उपार्जन हो, इसके लिए ऑनलाइन निगरानी की व्यवस्था बनाई गई है। राज्य और जिला स्तर पर उपार्जन पोर्टल पर दर्ज होने वाली उपज संबंधी जानकारी के आधार पर आकलन किया जाएगा। यदि उपज में कचरा, टूटन या नमी अधिक होती है तो उसे लौटा दिया जाएगा। जब किसान उपज ठीक कराकर निर्धारित मापदंड के अनुसार लाएगा, तब ही उसे स्वीकार किया जाएगा।

नमी मापक यंत्र रखे जाएंगे: दरअसल, धान किसान से लेने के बाद उसे चावल बनाने के लिए मिलर्स को दी जाती है। उस समय कई बार नमी, कचरा और टूटन अधिक होने की शिकायत सामने आती है। ऐसी उपज मिलर्स नहीं लेते हैं, क्योंकि प्रति क्विंटल धान से 67 किलोग्राम चावल लिया जाता है। जब यह मात्रा नहीं मिलती है तो मिलर्स को नुकसान होता है। यही कारण है कि इस बार गुणवत्तायुक्त उपज की खरीदी पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सभी केंद्रों पर नमी की जांच करने के लिए नमी मापक यंत्र रखे जाएंगे।

मिलिंग भी समय पर होगी

नमी जांचने के बाद धान लेकर सीधे उपार्जन केंद्र से ही मिलिंग के लिए मिलर्स को दी जाएगी। इससे परिवहन और भंडारण व्यय में कमी आने के साथ मिलिंग भी समय पर होगी। भारतीय खाद्य निगम ने मिलिंग के लिए अंतिम सीमा जून रखी है। उपार्जन के दौरान या उसके बाद होने उपार्जन में होने वाली गड़बड़ियों को रोकने के लिए खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, प्रमुख सचिव रश्मि अरुण शमी और आयुक्त सिबि चक्रवर्ती औचक निरीक्षण करेंगे। किसी भी स्तर पर लापरवाही या अनियमितता पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उड़नदस्ते भी जिला स्तर पर गठित होंगे, जो उपार्जन केंद्रों का निरीक्षण करेंगे।

श्योपुर जिले में धीमा चल रहा फॉर्मर रजिस्ट्री और यूनिक आईडी बनाने का काम

एक लाख का लक्ष्य, बन पाई सिर्फ 5 हजार के आसपास फॉर्मर रजिस्ट्री-यूनिक आईडी

श्योपुर। जागत गांव हमार

राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में किसानों का डेटाबेस तैयार करने के लिए फॉर्मर रजिस्ट्री आईडी बनाई जा रही है। इसके लिए राजस्व विभाग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। श्योपुर जिले में एक लाख 04 हजार किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री बनाने लक्ष्य रखा गया, लेकिन इसकी तुलना में 5 दिसंबर तक सिर्फ 5 हजार के आसपास ही किसानों की आईडी बन पाई है। 15 दिसंबर तक रजिस्ट्रेशन होंगे। लेकिन अभी श्योपुर जिले में यह आइडी बनाने का काम काफी धीमा चल रहा है। हालांकि इस संबंध में जिले के जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी नाराजगी जताते हुए राजस्व अमले को काम में गति लाने के निर्देश दिए थे। लेकिन इसके बाद भी काम फिलहाल गति आती नहीं दिख रही है। अधिकारिक सूत्रों के अनुसार हर किसान का आईडी कार्ड बनाया जा रहा है, जिससे उसकी पहचान हो सकेगी। फॉर्मर रजिस्ट्री के आधार पर ही किसानों को केंद्र और राज्य सरकार की कृषि योजनाओं का लाभ मिलेगा।

1 लाख 4 हजार किसानों यूनिक आईडी बनेगी- यूं तो जिले में 89 हजार के आसपास किसान पीएम किसान सम्मान निधी का लाभ ले रहे है, लेकिन यूनिक आईडी 1 लाख 4 हजार किसानों की बनाए जाने का लक्ष्य निर्धारित है। बता दें कि अगर किसी किसान के खेत अलग-अलग है तो उनकी खाता संख्या व खतौनी भी अलग होती है। इससे किसी भी योजना का फायदा किसानों को देने के लिए उनका सत्यापन करना पड़ता है। इस परेशानी को दूर करने के लिए अब किसानों की फॉर्मर रजिस्ट्री बनाने के साथ ही उनका यूनिक आईडी भी बनाई जाएगी। इसके लिए खसरा खतौनी में दर्ज अभिलेख का उपयोग किया जाएगा।

एक नजर में फायदे

- पीएम किसान योजना की किस्त प्राप्त करने में आसानी होगी।
- किसान क्रेडिट कार्ड, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रचर फंड और अन्य कृषि विकास लोन प्राप्त कर सकेंगे।
- फसल बीमा का लाभ भी आसानी से मिल सकेगा। आपदा की स्थिति में क्षति पूर्ति राशि के लिए किसानों को चिह्नित करना आसान होगा।
- न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए किसानों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकेगा।
- सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने में आसानी होगी। बार-बार सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी।

फॉर्मर रजिस्ट्री के लिए किसानों को रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। सरकार की समस्त योजनाओं का लाभ किसानों को फॉर्मर रजिस्ट्री के आधार पर ही मिलेगा। लगातार इस कार्य की मॉनिटरिंग कर रहे हैं।
एमएस गुर्जर, अधीक्षक भूअभिलेख श्योपुर

कृषि चौपाल के प्रथम एपिसोड का प्रसारण, समूह चर्चा में मिला सवालों का समाधान

भोपाल। कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग ने दूरदर्शन और आकाशवाणी के सहयोग से रिकॉर्डेड किसान-वैज्ञानिक इंटरफेस के माध्यम से किसानों के बीच उन्नत प्रौद्योगिकी सूचना के प्रसार के लिए एक मंच बनाने के लिए कृषि चौपाल कार्यक्रम शुरू किया है। जिसका प्रथम एपिसोड का प्रसारण डीडी किसान चैनल पर शनिवार को किया गया, जिसमें कृषि विज्ञान केन्द्र पोकरण पर किसान गोष्ठी के आयोजन कर क्षेत्र के 53 कृषि स्नातकों एवं किसानों को कार्यक्रम से जोड़ा गया।

इस कार्यक्रम में देश के विभिन्न क्षेत्रों में रबी मौसम के लिए उपयुक्त 109 उन्नत किस्में रिलीज की गई एवं इन किस्मों की विशेषताओं की जानकारी चर्चा का प्रमुख केंद्र रहा। कार्यक्रम में केन्द्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं अध्यक्ष डॉ दशरथ प्रसाद ने कार्यक्रम की उपयोगिता से किसानों को अवगत कराया एवं प्रतिभागियों को नवाचारों को अपनाने की बात कही। सस्य वैज्ञानिक कृष्ण गोपाल व्यास ने उन्नत किस्मों की अहमियतता को किसानों के साथ साझा किया। कार्यक्रम में पशुपालन वैज्ञानिक डॉ राम निवास ने शुष्क क्षेत्रो में बकरी पालन, भेड़ पालन, गाय पालन करने पर जोर दिया। केन्द्र के प्रसार वैज्ञानिक सुनील शर्मा ने समन्वित कृषि प्रणाली की विशेषताओं की चर्चा की तथा इसे अपनाने की बात कही। कार्यक्रम के अंत में प्रतिभागियों के साथ समूह चर्चा के माध्यम से सवालों का उचित समाधान दिया गया।

देश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाये जाने की असीम संभावनाएं: डॉ. सिंह

केवीके पर 'राष्ट्रीय दुग्ध दिवस' का आयोजन
भारत के केंद्र में किसान एवं गांव
दुग्ध उत्पादन में तेजी से उभर रहा है मध्य प्रदेश

लहार (भिंड)। भारत दुनिया का सर्वाधिक दूध पैदा करने वाला देश है। लेकिन विश्व की सर्वाधिक पशु संख्या होने के बावजूद उसकी तुलना में जितना दूध पैदा होना चाहिए वह हो नहीं रहा है। इसके पीछे की प्रमुख वजह पशुओं की उन्नत नस्ल नहीं होना तथा चारे-दाने का अभाव है। यह जानकारी कृषि विज्ञान केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक प्रमुख डॉ. एसपी सिंह द्वारा केंद्र पर आयोजित राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के अवसर पर किसानों के बीच दी गई।

डॉ. एसपी सिंह ने बताया के वर्तमान में भारत में 235 मिलियन टन से अधिक दूध उत्पादन हो रहा है। विश्व में भारत दूध उत्पादन में नंबर एक पर आता है तथा पूरे विश्व का लगभग 25 प्रतिशत दूध भारत मैं ही पैदा होता है। राज्यों की बात करें भारत में पांच सबसे ज्यादा दूध पैदा करने वाले राज्यों में क्रमश: उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात तथा आंध्र प्रदेश आते हैं। उन्होंने बताया कि अभी देश में दुधारू पशुओं की संख्या को देखते हुए बहुत कम दूध पैदा हो रहा है। इसको उन्नत नस्ल के पशु पालन, समुचित मात्रा में आहार एवं रोग प्रबंधन कर उच्चतम स्तर तक ले जाया जा सकता है। उन्होंने कहा किसानों को स्वयं दूध पैदा करने के साथ दूध दही मट्ठा आदि का प्रयोग भी करना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश राज्य दुग्ध उत्पादन में तेजी से उभरता हुआ राज्य बन रहा है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला प्रचारक राजपाल सिंह ने कहा के पुरातन काल में लोगों को आशीवाज्द देते समय भी दूध का जिक्र किया जाता था। आज की पीढ़ी दूध से दूरी बना रही है दूध एक संतुलित आहार है जो गांव मैं किसान के भोजन का मुख्य आधार भी है। उन्होंने कहा कि भारत का केंद्र किसान एवं गांव है इसलिए किसान समृद्ध होगा तो गांव समृद्ध होंगे और गांव समृद्ध होगा तो देश समृद्ध बनेगा।

दुग्ध उत्पादन और पशुपालन इसमें सकारात्मक भूमिका निभा सकते हैं। विदित हो कि श्वेत क्रांति के जनक डॉ। वागीश कुरियन के जन्मदिन को हर वर्ष राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी परिपेक्ष में कृषि विज्ञान केंद्र पर निकरा परियोजना अंतगत्त राष्ट्रीय दुग्ध दिवस का आयोजन किया गया था। इस अवसर पर संविधान दिवस के चलते कार्यक्रम में उपस्थित वैज्ञानिकों, अतिथियों एवं किसानों को संविधान की शपथ भी दिलाई गई।

ग्रामीण महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में सशक्त बनाने और बाजार विस्तार के लिए एब्सोल्यूट ग्राम्या और जेराइज अलायंस के बीच हुआ समझौता

भोपाल। जागत गांव हमार

ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, एब्सोल्यूट ग्राम्या और जेराइज अलायंस प्राइवेट लिमिटेड ने एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने और उनके उत्पादों के बाजार विस्तार में सहयोग करेंगी। दोनों कंपनियां एक-दूसरे के उत्पादों के विपणन में सहयोग करेंगी और लाभ मार्जिन को बढ़ाने के लिए रणनीतियां विकसित करेंगी, ग्रामीण महिलाओं को उद्यमी बनाने के लिए नए मॉडल विकसित किए जाएंगे। कंपनियां अपने वेबसाइटों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को एब्सोल्यूट ग्राम्या के भौतिक स्टोर और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जोड़कर मार्केटिंग नेटवर्क का विस्तार करेंगी। महिलाओं को उद्यमिता के क्षेत्र में प्रशिक्षित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। दोनों कंपनियां आपसी लाभ के लिए अन्य सामान्य हित के क्षेत्रों में भी सहयोग करेंगी।

इस समझौते के साथ, दोनों कंपनियां ग्रामीण भारत में मार्केटिंग उद्यमिता को बढ़ावा देने और ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं। वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल 5 हजार महिलाओ को मार्केटिंग के क्षेत्र में स्वरोजगार में परिक्षण दे कर स्वालाम्भी बनाया जाएगा ,ग्रामीण भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने और ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठा रही हैं।

मार्केटिंग के लिए विकसित शक्ति ऐप एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो ग्रामीण महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। यह प्लेटफॉर्म उन्हें बिना किसी शुरुआती निवेश के अपना व्यवसाय शुरू करने और बढ़ाने में सहायता करता है। यह तकनीक का उपयोग करके व्यवसाय प्रबंधन और उत्पाद वितरण को आसान, कुशल और लाभदायक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है।

-ग्वालियर-चंबल और आगर-मालवा के 13 जिलों में होगा पानी ही पानी

पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना पर एमपी-राजस्थान सहमत

भोपाल। जागत गांव हमार

- पार्वती-कालीसिंध-चंबल के जुड़ने से दोनों राज्यों को फायदा होगा
- समझौता ज्ञापन पर इस साल जुलाई में हो चुके हैं हस्ताक्षर
- परियोजना के लिए एमओपी पर हस्ताक्षर करेंगे दोनों राज्य

पार्वती-कालीसिंध-चंबल परियोजना का काम शुरू करने के लिए मध्य प्रदेश और राजस्थान की राज्य सरकारों के बीच मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किया जाएगा। प्रदेश के नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने मंत्रालय में जानकारी दी कि मध्य प्रदेश और राजस्थान की सरकारें पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदी जोड़ो परियोजना पर एमओपी पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गई हैं। एमओपी पर हस्ताक्षर होते ही दोनों पड़ोसी राज्यों के बीच नदियों को जोड़ने (पार्वती-कालीसिंध-चंबल) की महत्वपूर्ण परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा। इस परियोजना के लिए 75 हजार करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर इस साल जुलाई में ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। अब दोनों राज्यों के बीच जल्द ही एमओपी पर हस्ताक्षर किया जाएगा। मंत्री विजयवर्गीय ने बताया कि यह परियोजना मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल और आगर-मालवा क्षेत्रों के 13 जिलों को पानी उपलब्ध कराएगी। इससे दोनों राज्यों में कम से कम 2.8 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई में भी मदद मिलेगी। इस साल जुलाई की शुरुआत में मध्य प्रदेश की यात्रा के दौरान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा था कि नदी जोड़ परियोजना से दोनों राज्यों को फायदा होगा, जिससे राज्यों के बीच संबंध भी मजबूत होंगे।

पार्वती का विशेष योगदान

पार्वती नदी मप्र और राजस्थान से बहने वाली चंबल नदी की तीसरी सबसे बड़ी सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में आष्टा के पास 609 मीटर की ऊंचाई पर विंध्याचल पर्वतमाला से निकलती है और राजस्थान के कोटा जिले में चंबल नदी में मिलती है।

-पंचायत मंत्री प्रह्लाद बोले-भिंड जिले के ग्राम नुन्हाटा में बनेगा फूड पार्क

भिंड को समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में फूड पार्क अहम कदम

भोपाल। जागत गांव हमार

पंचायत एवं ग्रामीण विकास, श्रम एवं भिण्ड जिले के प्रभारी मंत्री प्रह्लाद सिंह पटेल के मुख्य आतिथ्य में भिंड में पहली बार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम जिला पंचायत कार्यालय के सभागृह में आयोजित किया गया। इस अवसर पर नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला सहित विधायक, जनप्रतिनिधि, कलेक्टर, इन्वेस्टर्स, विभिन्न बैंकों के अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री पटेल ने कहा कि फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में निवेश की अपार संभावनाएं हैं। इससे न केवल किसानों की आय बढ़ेगी, बल्कि अपार संभावनाएं भी खुलेंगी। इस क्षेत्र में निवेश जिले की कृषि उत्पादकता को बढ़ाएगा।किसानों की आय में वृद्धि होगी और मूल्य संवर्धन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त होगी। ऐसे प्रयास जिले को आर्थिक रूप से समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। निवेशकों की हर संभव मदद की जाएगी है। उन्होंने निवेशकों को आश्वस्त किया कि सरकार राज्य में विभिन्न उद्योगों में निवेश बढ़ाने के लिए पूर्णत: प्रतिबद्ध है, मध्यप्रदेश को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाने का हरसंभव प्रयास किया जा रहा है। ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला ने कहा कि भिंड के ब्रांड को दुनिया में पहुंचाने की जरूरत है। जनप्रतिनिधियों और जिला प्रशासन के लगातार प्रयासों से एमएसएमई विभाग के अंतर्गत ग्राम नुन्हाटा में 300 हेक्टेयर भूमि पर फूड पार्क प्रस्तावित है। इन्वेस्टर्स मीट कार्यक्रम में बताया गया कि जिले के औद्योगिक विकास एवं रोजगार को सृजित करने के उद्देश्य से यह फूड पार्क विकसित किया जा रहा है, जिसका लाभ जिले के किसानों को मिलेगा एवं उन्हें प्रशिक्षण के माध्यम से प्राकृतिक खेती, सब्जियों की इंटरक्रापिंग, फलोद्यान विकास के लिये प्रोत्साहित किया जाएगा। कृषि उत्पाद आदि की बिक्री एवं अच्छे दाम दिलवाने की व्यवस्था फूड पार्क में उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों के साथ लिंक कर की जाएगी, जिससे कृषक क्राप डायवर्सिफिकेशन, वेजीटेबल इंटरक्रापिंग के प्रति भी आकर्षित होकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकें।

विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाएंगे

फूड पार्क कन्वर्जेंस मॉडल पर आधारित रहेगा, जिसके तहत फूड प्रोसेसिंग से संबंधित विभिन्न प्रकार के उद्योग स्थापित किए जाएंगे, जिससे लगभग 5 हजार से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। परियोजना के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नाबार्ड से सब्सिडी, अनुदान आदि के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे बेहतर उपकरण, इंक्यूबेशन सेंटर, कॉमन फैसिलिटेशन सेंटर, खाद्य उत्पादों की सैंपलिंग,टैस्टिंग, पैकेजिंग आदि की बेहतर सुविधा फूड पार्क में ही उपलब्ध हो सके। समिट में एमएसएमई, एपीडा, डीजीएफटी आदि के विशेषज्ञ इन्वेस्टर्स को विभिन्न फूड प्रोसेसिंग से एवं इंडस्ट्री से संबंधित विभिन्न लाभकारी योजनाओं के संबंध में जानकारी साझा की गई।

किसान आंदोलन के बीच धनखड़ ने की तारीफ, कहा

शिवराज सिंह देश के लाड़ले किसानों के भी लाड़ले बनेंगे

भोपाल। जागत गांव हमार

राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने दो दिन पहले ही किसान आंदोलन के मुद्दे पर केंद्रीय कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को आड़े हाथ लिया था। अब सभापति का मिजाज बदला-बदला नजर आया और उन्होंने शिवराज की तारीफ की। किसान एक बार फिर आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली आने की कोशिश में जुटे हैं। इस बीच, राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की तारीफ की। शंभू बॉर्डर पर जुटे किसानों का मुद्दा राज्यसभा में उठा तो सभापति ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान देश के लाड़ले हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि वे किसानों के भी लाड़ले बनेंगे। अपने नाम के अनुरूप काम करेंगे। सभापति ने कांग्रेस के रुख पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मुझे खुशी होती कि जयराम रमेश किसानों के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव लाते और चर्चा करते। मैं बता दूं कि मंत्री (शिवराज सिंह चौहान) आते समय और जाते समय भी मेरे साथ थे और मुझे विश्वास है कि जो व्यक्ति देश में लाड़ला के नाम से जाना जाता था, वह किसान का भी लाड़ला होगा। मुझे उम्मीद थी कि जयराम रमेश सवाल पूछेंगे और अच्छा लगेगा कि एक स्थगन प्रस्ताव किसान मुद्दे पर भी आएगा, लेकिन नहीं आया।

लाड़ली के नाम से थी शिवराज की पहचान

राज्यसभा स्पीकर जगदीप धनखड़ ने कहा कि मंत्री जी आते-जाते समय मेरे साथ थे। मैंने मंत्री से कहा और मैं आश्वस्त हुआ जिस आदमी की पहचान देश में लाड़ली के नाम से थी वो किसान का लाड़ला होगा। मैं पूरी तरह आशावान हूं कि ऊर्जावान मंत्री अपने नाम शिवराज के अनुरूप, ये करके दिखाएंगे। जयराम रमेश से मुझे उम्मीद थी कि वो कोई प्रश्न पूछेंगे। बड़ा अच्छा लगता अगर एक बार भी एडजर्नमेंट मोशन आता। लेकिन एक भी प्रश्न आया नहीं। आज मैंने आपका नामांकन कर दिया है किसान के लाड़ले।

पौधों में डाल सकते हैं नई जान, अब रॉकेट की रफ्तार से बढ़ेंगे पौधे

खाद भूल जाओ! चाय पत्ती से फ्री में लहलहा उठेगा गार्डन

भोपाल। जागत गांव हमार

गार्डनिंग करने वाला हर शख्स चाहता है कि उसके घर पर लगे पौधे पड़ोसी के गार्डन से अधिक ग्रोथ करें। गार्डन का खयाल रखने के लिए लोग महंगे-महंगे फर्टिलाइजर भी मंगाते हैं, लेकिन कई बार जलवायु और सही वातावरण का संतुलन मैच नहीं हो पाता जिसके चलते बाजार में बिकने वाले फर्टिलाइजर से फायदे नहीं मिलते हैं। गार्डन में हमेशा ऑर्गेनिक और देसी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑर्गेनिक गार्डनिंग करने पर मिलने वाली पैदावार की गुणवत्ता अधिक अच्छी होती है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद है। आज आपको फ्री में बनने वाली चाय पत्ती की खाद के बारे में बताते हैं जिसका इस्तेमाल करके आप अपने पौधों में नई जान डाल सकते हैं। हमारे देश के लोग चाय को सिरदर्द की दवा के रूप में भी इस्तेमाल कर लेते हैं। चाय के दीवाने आपको चाय पीने के इतने फायदे और उसके गुण गिनवा देंगे कि उंगलियां कम पड़ जाएंगी। चाय हमारे लिए फायदेमंद है या नहीं, इसपर हम कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन चाय छानने के बाद बची चाय पत्ती पौधों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। आइए इसके फायदे जान लेते हैं...।

मिट्टी की संरचना में सुधार| चाय पत्ती से बनी खाद मिट्टी की हेल्थ के लिए बहुत फायदेमंद है। ये बहुत ही आसानी से मिट्टी में मिलकर उसकी गुणवत्ता को बढ़ाती है। इतना ही नहीं, मिट्टी में ऐयरेशन को भी बढ़ावा देती है। चाय पत्ती से बनी खाद जल निकासी को बेहतर बनाती है। ये मिट्टी के पीएच को एसिडिक बनती है जो पौधों के लिए फायदेमंद है।

पौधों की ग्रोथ में असरदार| चाय की पत्तियों में अमीनो एसिड, मल्टीविटामिन और सूक्ष्म तत्व होते हैं। ये तत्व किसी भी पौधों को बढ़ाने में सहायक होते हैं। चायपत्ती की खाद का इस्तेमाल करने पर पौधों में नाइट्रोजन की मात्रा मिलती है, जिससे उन्हें अधिक पोषण मिलता है। इसके अलावा इस खाद में वो सभी पोषक तत्व होते हैं जिससे पौधों को फायदा होता है।

खाद बनाने का तरीका

चाय पत्ती की खाद के जितने फायदे हैं उससे भी आसान इसको बनाने का तरीका है। आप लगभग एक हफ्ते तक चाय छानने के बाद बची चायपत्ती को इकट्ठा कर लीजिए। अब चाय पत्ती को अच्छी तरह धो लें ताकि उसके दूध और शक्कर अच्छी तरह धुल कर निकल जाए। अब इन पत्तियों को लगभग दो दिन अच्छी तरह धूप में सुखा लीजिए। अब दो चम्मच खाद डालें। इसके अलावा एक बोतल पानी में दो चम्मच चाय पत्ती खाद डालकर पानी में 2 दिन तक घोलें और गमले में डालें। इन दोनों तरीकों का इस्तेमाल पौधों में कर सकते हैं।

ध्यान रखें ये बातें

चाय की पत्ती से बनी खाद का तरीका भी बहुत आसान है और इसके फायदे भी खूब हैं, लेकिन चाय पत्ती से बनी खाद का गलत इस्तेमाल करने पर पौधों में बुरा असर देखने के भी मिल सकता है। इस खाद में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इसका जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करने पर पौधे झुलस जाते हैं। छोटे पौधों में एक चम्मच और बड़े पौधों में दो चम्मच से अधिक खाद ना दें। हर महीने भी इस खाद का यूज करने से बचें।

ग्रामीण क्षेत्र में ऋण का बढ़ता स्तर चिंता का विषय

भारत के एफएमसीजी क्षेत्र में जुलाई-सितंबर तिमाही में मूल्य के हिसाब से 5.7 प्रतिशत और कारोबार के हिसाब से 4.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो ग्रामीण क्षेत्रों की मांग की बदौलत संभव हुआ है। कंज्यूमर इंटेलिजेंस फर्म नील्सनआईक्यू ने हाल ही में अपनी तिमाही रिपोर्ट में यह जानकारी दी। लेकिन कई लोगों का मानना है कि भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ऋण का बढ़ता स्तर चिंता का विषय है।

हमारे देश भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में ऋण का बढ़ता स्तर चिंता का विषय है। कुछ गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) ऐसी स्थिति के बावजूद दांव आजमाने की कोशिश करते हुए हालात को और जटिल बना रही हैं। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने 'दबाव देकर दिए जाने वाले ऋण' के बढ़ते मामले पर अब ध्यान देना शुरू किया है। ऐसे ऋणों की मार्केटिंग बेहद आक्रामक तरीके से ऐसे की जाती है कि ऋण लेने वाले इनके दीर्घकालिक वित्तीय परिणामों से वाकिफ नहीं हो पाते हैं।

ऋण संकट के मूल कारणों में से एक, देश के ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के पर्याप्त अवसरों का अभाव है। आर्थिक वृद्धि का लाभ भी पर्याप्त रूप से रोजगार सृजन में नहीं दिखा है, खासतौर पर गैर-कृषि क्षेत्रों में। ऋण की आसान पहुंच और चौबीस घंटे डिलिवरी सेवाओं के प्रसार से ग्रामीण क्षेत्रों में खपत की स्थिति बढ़ी है। लोगों को गैर- जरूरी वस्तुओं और सेवाओं के वास्ते ऋण लेने के लिए लुभाया जा रहा है जिससे ये और अधिक कर्ज के जाल में फंस रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के परिवार, रोजमर्रा की अपनी जरूरतों के लिए भी ऋण की राशि पर निर्भर हो रहे हैं।

ग्रामीण अर्थव्यवस्था में आय के स्रोत अनिश्चित हैं और यह मुख्य रूप से कृषि पर निर्भर है। यह अप्रत्याशित मानसून, जिंसों की उतार-चढ़ाव वाली कीमतों और बढ़ती इनपुट लागत से भी प्रभावित होती है। कुछ एनबीएफसी इस अंतर का फायदा उठा रहे हैं और रोजमर्रा की खपत के लिए ऋण अधिक ब्याज दरों पर देते हैं। इसमें ऋणों का रॉलओवर चक्र एक अहम हिस्सा है।

इसका सबसे बड़ा संस्थागत उदाहरण फसल ऋण है। सरकार हर वर्ष, किसानों को फसल ऋण का वितरण करने के लिए बैंकों के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करती है। इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए बैंकों पर दबाव होता है जिसके कारण अवसर ऋणों का वितरण तेजी से यह सुनिश्चित किए बिना ही कर दिया जाता है कि इनका उपयोग उत्पादक तरीके से किया जाएगा या नहीं। इस ऋण का इस्तेमाल उत्पादक कृषि निवेश के लिए किए जाने के बजाय, तत्काल जरूरतों को पूरा करने या पुराने ऋण का भुगतान करने के लिए किया जाता है जिससे ग्रामीण ऋण संकट गहरा जाता है।

अब यह प्रथा सामान्य एनबीएफसी के साथ-साथ माइक्रो फाइनेंस से जुड़े लोगों तक फैल गई है। वे ऋण का रॉलओवर कर रहे हैं, जिससे उधारकर्ताओं को और अधिक कर्ज में धकेला जा रहा है।

एनबीएफसी ने ग्रामीण क्षेत्रों में औपचारिक बैंकिंग क्षेत्र की सीमित पहुंच के कारण बनी अंतराल जैसी स्थिति को भरने के मकसद हालांकि, उनकी ब्याज दरें अक्सर बैंकों

द्वारा लगाए जाने वाली ब्याज दरों से कहीं अधिक होती हैं और यह ऋणकर्ताओं पर अतिरिक्त बोझ डाल रही हैं। आरबीआई ने अधिक ब्याज दरों को लेकर चिंता जताई है खासतौर पर सूक्ष्म ऋणों के संदर्भ में। जब बैंकिंग नियामक ने मार्च 2022 में ब्याज दरों को मुक्त कर दिया, उसके बाद पिछले कुछ वर्षों से ऐसा हुआ है क्योंकि पहले ऋण दरें, फंड की लागत से जुड़ी हुई थी। एक बार जब इसे मुक्त कर दिया गया तब लगभग सभी सूक्ष्म ऋणदाताओं ने दरों में बढ़ोतरी की। शुरुआत में, यह बहाना दिया गया था कि कोविड की अवधि के दौरान हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए कुछ और कमाई करने की जरूरत थी। इस वक्त ऐसा कोई बहाना नहीं है।

कुछ बैंक जिनकी सार्वजनिक जमाओं तक कम लागत के साथ पहुंच है वे भी एनबीएफसी की तुलना में कभी-कभी सूक्ष्म ऋण पर, उच्च ब्याज दर वसूल रहे है। अगर एनबीएफसी की जांच-पड़ताल उनके ब्याज दरों के लिए की जा रही है तब क्या इस लिहाज से बैंकों की जांच नहीं की जानी चाहिए? ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण की लागत कर्ज लेने वाले की भुगतान क्षमता के मुकाबले गैर-आनुपातिक तरीके से बढ़ रही है जिसके चलते फण का चक्र और जटिल हो रहा है।

ग्लोबल डेवलपमेंट इन्क्यूबेटर (जीडीआई) की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक ग्रामीण क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक लोगों की आमदनी का प्राथमिक स्रोत खेती है लेकिन इनमें से अधिकांश लोग बेहतर मौके पाने के लिए खेती छोड़ने के लिए तैयार हैं। ग्लोबल ऑपर्च्यूनिटी युथ नेटवर्क डेवलपमेंट इंटेलिजेंस यूनिट और ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया फाउंडेशन की साझेदारी से तैयार की गई, 'स्टेट ऑफ रूरल यूथ इम्प्लॉयमेंट- 2024' की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के ग्रामीण हिस्से में तकरीबन 5,000 लोगों का सर्वेक्षण किया गया जिनमें से 70-85 फीसदी लोगों का कहना है कि वे किसी विनिर्माण, रिटेल या कारोबारी क्षेत्र में नौकरी करना चाहते हैं।

रिपोर्ट लॉन्च करते हुए भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन ने कहा, 'कृषि को वृद्धि का इंजन होना चाहिए और फिर से इसका चलन बढ़ना चाहिए।' गैर लाभकारी संस्थानों, उद्योग और अकादमिक जगत के लोगों को सहयोग कर इस क्षेत्र को रोजगार के लिहाज से व्यवहारिक विकल्प के तौर पर पेश करना चाहिए।

देश के ग्रामीण क्षेत्र में बढ़ते ऋण के संकट को लेकर कुछ बातों पर ध्यान देने की आवश्यकता है और इसके लिए विचार करने के लिए कुछ प्रमुख मुद्दों पर ध्यान देना जरूरी है।

रोजगार सृजनः उपभोग की जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋण पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए रोजगार के टिकाऊ अवसर तैयार करने की जरूरत है।

ऋण उपयोगिताः ऋण वितरण के बड़े लक्ष्य तय करने के बजाय सरकार और वित्तीय संस्थानों को यह सुनिश्चित करने पर ध्यान देना चाहिए कि ऋणों का इस्तेमाल विशेषतौर पर कृषि में बेहद उत्पादक तरीके से किया जाता है।

ब्याज दरों का नियमनः आरबीआई को यह सुनिश्चित करने की जरूरत है कि एनबीएफसी और बैंक, किफायती ब्याज दरों पर ऋण की पेशकश करें।

जागरूकता और वित्तीय साक्षरताः ग्रामीण ऋणकर्ताओं को अधिक ऋण लेने के नतीजे और वित्तीय योजना की अहमियत के बारे में जागरूक करने की जरूरत है। अगर इन मसलों का हल व्यापक तरीके से नहीं किया जाता है तब ग्रामीण क्षेत्र की ऋण वृद्धि जारी रह सकती है और इसके दूरगामी आर्थिक और सामाजिक परिणाम हो

पशुओं में अम्लीकरणः कारण और उसका निवारण

» डॉ. संजू मंडल
» डॉ. अनिल गट्टानी
» डॉ. शुभ्रदल नाथ
» डॉ. अनिल गट्टानी
» डॉ. अमित कुमार
» डॉ. आफरीन खान
» डॉ. आनंद कुमार जैन
» डॉ. प्रगति पटेल
» डॉ. पूर्णिमा सिंह
» डॉ. आदित्य मिश्रा
- पशुचिकित्सा एवं पशुपालन महाविद्यालय, जबलपुर, मप्र

देखा गया है कि लोग अपने घर में पाले हुए पशु जैसे गाय, भैंस आदि को रात का बचा हुआ भोज्य पदार्थ सुबह खिला देते हैं। ऐसा करने से उनको अम्लीकरण की शिकायत हो जाती है, अर्थात अम्ल का अधिक उत्पादन। कभी-कभी तो अम्ल का उत्पादन इतना अधिक हो जाता है कि यदि समय रहते उपचार न किया जाये तो 28 घंटे के भीतर पशुओं की मृत्यु तक हो जाती है। जुगाली करने वाले पशु चूंकि अधिक वसा और कार्बोहाइड्रेट वाला भोज्य पदार्थ ग्रहण करने के आदी नहीं होते हैं। वो शीघ्र ही अम्लीकरण के शिकार हो जाते हैं।

अम्लीकरण के दौरान रूमन (जुगाली करने वाला पेट या पेट नं. 1) में उपस्थित अमाइलोलाइटिक जीवाणु अनाज का किण्वन कर देते हैं और निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं: **1.** बारह घंटे के अंदर लेक्टिक अम्ल का अधिक उत्पादन होता है। **2.** बारह से चैबीस घंटे के बीच रूमन के द्रव का पी.एच. कम हो जाता है। **3.** वाष्पशील वसा अम्ल की आर्दता 12 घंटे के बाद बढ़ जाती है। पूर्ण रूप से और तेजी से स्टार्च का किण्वन होने पर लेक्टिक अम्ल और वसा अम्लों का अधिक उत्पादन होता है और रूमन के द्रव का पीएच कम हो जाता है। इसके फलस्वरूप रूमन में उपस्थित प्रोटोजोआ अदृश्य हो जाते हैं। रूमिनाइटिस या रूमन की सूजन के दौरान बने रसायन रूमन की दीवार को तोड़ देते हैं और जीवाणु और फफूंद खून में प्रवेश कर जाते हैं और इस तरह से भी रूमन में अधिक अम्ल का उत्पादन अम्लीकरण के दौरान खून में लेक्टिक अम्ल का उत्पादन 12 से 48 घंटे के अंदर बढ़ जाता है और पीएच 12 से 48 घंटे के भीतर कम हो जाता है। बारह घंटे में अमाइलेज एन्जाइम की कार्यक्षमता बढ़ जाती है। अम्लीकरण से मूत्र में भी अम्ल की अधिकता पाई जाती है। कई विषैले पदार्थ जैसे हिस्टामिन, अल्कोहल, थायमिनेस और एन्डोटाक्सिन आदि अम्लीकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं और अवशोषित होते हैं। इससे लीवर को नुकसान होता है। लीवर काम करना बंद कर देता है और हिपेटोसाइटस सूज जाती है। साथ ही साथ लीवर में फोड़ा हो जाता है और लीवर की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं।

अम्लीकरण से प्रभावित पशुओं में निम्नलिखित लक्षण देखे जा सकते हैं: 1. पेट का अधिकतम फूल जाना। **2.** मुंह से झाग या लार का गिरना। **3.** खाना पीना, जुगाली बंद हो जाते हैं। **4.** कई बार पेशाब रूक जाती है। **5.** बीमार पशु शिकस्त हो कर लेट जाता है। **6.** आंख की पुतली फैल जाती है। **7.** म्यूकस की झिल्ली पीली पड़ जाती है। **8.** लीवर, गुर्दा और लिम्फोड बढ़ जाते हैं। **9.** त्वचा की सतह सूख जाती है और उसमें खिंचवा भी कम हो जाता है। **10.** रूमन के द्रव का रंग परिवर्तित हो जाता है। **11.** अधिक देर हो जाने पर उपचार कारगर नहीं हो पाता है।

अम्लीकरण का उपचारः अम्लीकरण के उपचार हेतु निम्नलिखित उपाय करने चाहिए: **1.** कारण पता हो जाने पर तुरन्त उपचार हेतु किसी कुशल पशुचिकित्सक को दिखाया जाये। **2.** 20 ग्राम खाने का सोडा एक लीटर पानी में घोल कर पिलायें या इन्जेक्शन से सीध रूमन में डालें। **3.** 5 प्रतिशत डेक्सड्रोज सेलाइन (2 से 3 लीटर) खून में देने से लाभ देता होता है। **4.** ग्लूकोज के इंजेक्शन को खाने के सोडे के घोल के साथ मिलाकर खून में देने से लाभ होता है। **5.** एविल का इंजेक्शन देने से फूले पेट में फायदा होता है। **6.** फार्मेलिन का घोल (प्रतिशत) रूमन में डालने से गैस का बनना रूक जाता है। **7.** टिम्पाल नामक दवा 50 से 100 ग्राम को पानी में मिलाकर लड्डू बनाकर खिलाने से आराम मिलता है।

कुत्तों में डायबिटीजः कारण, लक्षण और उचित देखभाल

» डॉ. शिवम सिंह मेहरोत्रा
» डॉ. आर.के बघेरवाल
» डॉ. एच.के मेहता
» डॉ. एके सोनी
» डॉ. ममता सिंह
» डॉ. पवन माहेश्वरी
-पशु चिकित्सा एवं पशु पालन महाविद्यालय महू, इंदौर, मप्र

कुत्तों में डायबिटीज एक आम लेकिन गंभीर और जटिल मेटाबोलिक विकार है, जो उनके स्वास्थ्य और जीवनशैली पर गहरा प्रभाव डाल सकती है। यह स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब पैंक्रियास पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन का उत्पादन नहीं कर पाता, या जब शरीर इंसुलिन को प्रभावी ढंग से उपयोग करने में असमर्थ होता है। इंसुलिन वह हार्मोन है, जो ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करने में सहायता करता है। इसके अभाव में रक्त में ग्लूकोज का स्तर असामान्य रूप से बढ़ जाता है, जो कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

डायबिटीज के कारणः कुत्तों में डायबिटीज के पीछे कई जैविक और पर्यावरणीय कारण हो सकते हैं। आनुवंशिकता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि कुछ नस्लों, जैसे पूडल, डॉबरमैन, डैशहाउंड और लैब्राडोर रिट्रीवर, में डायबिटीज का जोखिम अधिक होता है। इसके अलावा, मोटापा, हार्मोनल असंतुलन, बार-बार होने वाला पैंक्रियाटाइटिस, और असंतुलित आहार भी इस बीमारी को बढ़ावा देते हैं। अत्यधिक कार्बोहाइड्रेट और शर्करा से भरपूर भोजन कुत्तों में ग्लूकोज के स्तर को अस्थिर कर सकता है।

डायबिटीज के लक्षणः पहचान के संकेतः डायबिटीज के लक्षणों की शीघ्र पहचान बहुत आवश्यक है, ताकि समय पर उपचार शुरू किया जा सके। प्रमुख लक्षणों में अत्यधिक प्यास लगना, बार-बार पेशाब आना, अचानक वजन घटना, अत्यधिक भूख लगना, थकावट और सुस्ती, तथा दृष्टि संबंधी समस्याएं शामिल हैं। कुछ कुत्तों में, समय के साथ, मोतियाबिंद जैसे जटिलताएं भी विकसित हो सकती हैं।

डायबिटीज का निदान और उपचारः कुत्तों में डायबिटीज की पुष्टि के लिए पशु चिकित्सक रक्त और मूत्र की जांच करते हैं। ब्लड शुगर का उच्च स्तर और मूत्र में ग्लूकोज की उपस्थिति डायबिटीज का स्पष्ट संकेत है। उपचार में इंसुलिन थेरेपी मुख्य भूमिका निभाती है। इसके साथ ही, संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और ब्लड शुगर का लगातार मॉनिटरिंग आवश्यक है। कुत्तों के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए एंटी डायबिटिक आहार उपचार का अहम हिस्सा हैं। ये आहार फाइबर और प्रोटीन में उच्च और कार्बोहाइड्रेट में कम होते हैं, जो ब्लड शुगर को स्थिर रखने में मदद करते हैं।

एंटी-डायबिटिक डाइटः डायबिटिक कुत्तों के लिए आहार प्रबंधन बेहद महत्वपूर्ण है। फाइबर से भरपूर भोजन, जैसे हरी सब्जियां और शकरकंद, ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा कर सकते हैं। कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले खाद्य पदार्थ ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकते हैं। उच्च-गुणवत्ता वाले प्रोटीन, जैसे मांस, अंडा और मछली, ग्लूकोज को नियंत्रित रखने में सहायक होते हैं। साथ ही, ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व समग्र स्वास्थ्य को बेहतर बनाते हैं।

डायबिटीज से बचाव के उपायः डायबिटीज से बचाव के लिए कुत्तों की जीवनशैली और आहार में बदलाव आवश्यक है। वजन पर नियंत्रण रखना और पोषण युक्त संतुलित आहार देना प्राथमिक उपाय हैं। नियमित व्यायाम न केवल वजन को नियंत्रित रखता है, बल्कि ब्लड शुगर को भी स्थिर करता है। इसके अलावा, नियमित स्वास्थ्य परीक्षण और समय पर चिकित्सकीय परामर्श कुत्तों को इस बीमारी से बचाने में मदद करते हैं।

कुत्तों में डायबिटीज एक जटिल लेकिन प्रबंधनीय स्थिति है। सही समय पर उपचार, संतुलित आहार, और नियमित मॉनिटरिंग के माध्यम से कुत्तों को एक स्वस्थ और सक्रिय जीवन प्रदान किया जा सकता है। कुत्ते हमारे परिवार का हिस्सा हैं, और उनकी देखभाल करना हमारी जिम्मेदारी है। एक स्वस्थ जीवनशैली और समर्पित प्रयासों से आपका पालतू कुत्ता न केवल खुशहाल रहेगा, बल्कि दीर्घायु भी होगा।

बांधवगढ़ में विदेशों से प्यार का पैगाम लेकर आते हैं हजारों पक्षी

यहां होता है प्रवासी पक्षियों संगम

भारत मे ऋतुओं के साथ होने वाले परिवर्तन को लोक विज्ञान मे उंचा स्थान प्राप्त है। कांस के फूलने को वर्षा ऋतु के अवसान का संकेत माना जाता है। ठीक उसी तरह भारत आने वाले प्रवासी पक्षियों के बिना सर्दियों की कल्पना नहीं की जा सकती। यह अलग बात है कि आज की भाग-दौड़ भरी व्यस्तम जिंदगी मे हमारे पास पक्षियों के लिए समय न हो परंतु इनके क्रियाकलाप अत्यंत रोचक, रहस्मय और प्रेरणादायी होते हैं। यदि इसकी व्याख्या की किसी विशेषज्ञ से कराई जाए तो ये हम इंसानों से कहीं बेहतर और निष्कपट मिलेंगे। बगैर देरी, बगैर कोताही हर साल हजारों मील साइबेरिया से भारत का सफर तय करने वाले ये पक्षी घोंसला बनाते हैं। गृहस्थी बसाते हैं, अंडे देते हैं, बच्चों को बड़ा करते हैं और उत्तर और मध्य भारत की झुलसा देने वाली गर्मियां शुरू होने पहले विदा हो जाते हैं।

उमरिया। जागत गांव हमार

पक्षी प्रेमी और उनकी जीवन शैली के जानकार ऋषि भट्ट कहते हैं कि प्रवासी पक्षी दो प्रकार के होते है एक स्थानीय प्रवासी पक्षी और दूसरे मेहमान प्रवासी। स्थानीय प्रवासी पक्षी जो हिमालय जैसे भारत के सर्द मौसम वाले इलाकों से उडकर अपेक्षाकृत गर्म प्रदेशों मे चले जाते है। दूसरे प्रकार के प्रवासी पक्षी सुदूर उत्तर स्थित साइबेरिया से आते हैं, जो अधिकांश उत्तर और मध्य भारत के घने जंगलों मे डेरा डालते हैं। जिले के प्रसिद्ध बांधवगढ़ और घुनघुटी के जंगलों मे ये पक्षी अपनी आमद दे चुके हैं, जिन्हे सुबह और शाम जलाशयों के नजदीक देखा जा सकता है। वनों की मनोरम हरीतिमा, पक्षियों का कलरव और नदियों का कलकल राग मानों प्रकृति इन दिनों अपने पूणज़ यौवन का प्राप्त हो गई हो।

सच्चे प्रेमी होते हैं चंचल चितवन वाले खंजन- प्रेम या इश्क के नाम पर फरेब अब भले ही इंसान की फितरत बन गई हो, परंतु पक्षी कभी बेवफा नहीं होते और महबूब के नाम पर सब कुछ लुटा देते हैं। साथी के वियोग में सारस के प्राण त्याग देने का उल्लेख तो शास्त्रों मे मिलता ही है। दुनिया का सबसे बड़ा और अद्भुत कलावंत नर बया पक्षी तब तक घोंसले बनाता है। जब तक मादा को वह घोसला पसंद नहीं आ जाता। कजरारे चंचल नयनों वाले खंजन की दीवानगी भी किसी से कम नहीं। रह-रहकर सुरीली तान छेड़ने वाला खंजन तब तक गाता है, जब तक प्रेयसी प्रेमातुर होकर उसका अनुग्रह स्वीकार नहीं कर लेती है। भारत आने वाले प्रवासी पक्षियों मे शायद खंजन ही सबसे लोकप्रिय पक्षी है। खंजन इतना सुदर्शी होता है। मानो प्रकृति देवी ने फुरसत से इसका श्रृंगार किया हो। चंचल चितवन वाले खंजन के कजरारे नयनों की उपमा से हिंदी साहित्य अटा पड़ा है। रामचरित मानस मे गोस्वामी जी कहते है...।

जानि शरद ऋतु खंजन आए,
पाई समय जिमि सुकृत सुहाए।
जबकि मैथली शरण गुप्त के महाकाव्य साकेत में उर्मिला आयोध्या में आए खंजनों को देखकर कहती हैं-
निरख सखी ये खंजन आए, उन मेरे रंजन में नयन इधर मन भाए।

बादलों ने आसमान को अलविदा कह दिया है। जलाशयों का जल ठहर गया है। कुमुदनी, कमल खिलने लगे हैं। खेत-खलिहानों और घाटों मे खंजन इठलाने लगे हैं। खंजन को जलाशयों का वातावरण बहुत भाता है। बेहद शर्मीले खंजन को यहां दुम ऊपर नीचे करते देखा जा सकता है, जो इंसानों की आहट पाते ही फुर्र हो जाता है। भारत आकर खंजन प्रजनन करते हैं बच्चे पालते हैं और मई जून के पहले इनका जोड़ा हम सबको प्रेम और प्रीत की रीत सिखाकर हिमालय की ओर उड़ जाता है।

गरजती हैं बदूंके, चलते हैं तीर...

सर्दियों के सबाव पर आते ही झील, नदिया, ताल-तलैया प्रवासी पक्षियों के कलरव से गुलजार हो जाते हैं। प्रकृति की अद्भुत और अनुपम देन ये मेहमान परिंदे न केवल हमारे आकर्षण का केंद्र, बल्कि किसानों और पर्यावरण के मित्र भी होते हैं। बेहद भावुक, शर्मीले और निष्कपट होने के बावजूद ये इंसानों की क्रूर दृष्टि से नहीं बच पाते। प्रवासी पक्षियों पर कहीं बंदुकें गरजती हैं तो कही चिड़िमारों के तीर इनका सीना बेध देते हैं। भारत आने वाले कई प्रवासी पक्षी अपने वतन नहीं लौट पाते। मनुष्य की निर्मम और अमानवीय हरकत से कई पक्षियों का परिवार बिखर जाता है, तो कई विरह मे विहवल होकर दम तोड़ देते हैं। सुंदर-सलोने नन्हें पक्षियों की जान मांस भक्षियों के स्वाद और मुंह का निवाला बन जाती है तो कई जादू टोटके की भेंट चढ़ जाते हैं। यद्यपि वन और पर्यावरण विभाग इस पर नियंत्रण के दावे करते हैं, परंतु अब तब ये अप्रभावी और कमतर ही साबित हुए हैं।

घट रही प्रवासी पक्षियों की संख्या

पक्षियों के संरक्षण के प्रति प्रयत्नशील पक्षी प्रेमी और उनकी जीवन शैली के जानकर ऋषि भट्ट कहते हैं कि जिले मे साल दर साल प्रवासी पक्षियों की आमद घटती जा रही है। बिगड़ते पर्यावरण, घटते वन और जलस्त्रोतों के नजदीक इंसानी बसाहट के कारण पक्षियों को रहबसर का उपयुक्त वातावरण नहीं मिल रहा है। ऐसे मे संवेदनशील और शर्मीले स्वाभाव के पक्षी अब नजर नहीं आ रहे हैं। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि पर्यावरण के असंतुलन और विकरण के कारण पक्षियों की कई बेहद खूबसूरत और दुर्लभ प्रजातियां विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गई हैं।

मारें नहीं प्यार दें.....

पक्षियों की दुनिया अत्यंत रोचक और रहस्यमी है। पक्षी प्रकृति प्रदत बेहद खूबसूरत जीवी की श्रेणी मे आते हैं। बेजुबान होते हुए भी ये अत्यंत भावुक होते हैं, जो प्रेम, संवेदना और क्रूरता के अंतर को समझ सकते हैं। पक्षियों के साथ मानव के रिश्तों का उल्लेख प्राचीनतम ग्रंथों में भी मिलता है। इनकी कहानियां हमारी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा हैं। महाभारत, रामायण और ऋग्वेद की ऋचाओं मे पक्षियों का अद्भुत और रोचक चित्रण मिलता है। ये बेजुबान हमारे अतिथि हैं इन्हे मारे नहीं, प्यार दें, हमारी परंपरा भी तो है अतिथि देवो भव: की है।

देश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों में की गई कटौती के विरोध में कृषि विज्ञान केंद्रों के कर्मचारी संगठन 'केवा' (कृषि विज्ञान केंद्र एम्प्लोई वेलफेयर एसोसिएशन) के आह्वान पर देश के सभी कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारी पांच दिसंबर को एक दिवसीय कलमबंद हड़ताल पर रहे।

सेवा शर्तों में अचानक किए गए बदलाव से भड़का आक्रोश

केवीके के वैज्ञानिक-कर्मचारियों ने की देशव्यापी कलमबंद हड़ताल

रीवा। जागत गांव हमार

कृषि विज्ञान केन्द्र, रीवा मप्र में गत दिवस फोरम ऑफ केवीके एंड एआईसीआरपी द्वारा आयोजित आईसीए आर एवं नियोक्ता द्वारा केवीके के प्रति अन्याय के खिलाफ एक दिवसीय देशव्यापी विरोध प्रदर्शन हड़ताल की। हमारे अन्नदाता किसानों की प्राथमिक पाठशाला एवं कृषि के नवाचार को खेतों तक पहुंचने में पांच दशक तक केवीके के वैज्ञानिकों की अथक परिश्रम और प्रयासों का रिटर्न भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय द्वारा वैज्ञानिकों एवं कर्मचारियों को पिछले चार महीने से वेतन एवं अन्य राशि का भुगतान नहीं किया जा रहा है। वैज्ञानिक कर्मचारी पूर्ण रूप से हतोउत्साहित होकर अंतिम विकल्प के रूप में हड़ताल और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसा कि आज विश्व मृदा दिवस का अवसर है। ऐसे में हमारे किसानों को वैज्ञानिकों द्वारा समर्पित एवं सरल तरीके से कृषि के हर पहलू पर जानकारी दी जाती है। आज वैज्ञानिक मजबूरी बस हड़ताल एवं विरोध प्रदर्शन का कार्य कर रहा है। इस विषय पर भारत सरकार के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव एवं मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना को इस महत्वपूर्ण समस्या के समाधान के लिए शीघ्र ही कोई कारगर निर्णय लेते हुए देशव्यापी इस हड़ताल का कोई ना कोई शीघ्रतीशीघ्र समाधान निकालना होगा।

विभिन्न मांगों को लेकर भरी हुंकार

अटारी द्वारा केन्द्रों के कार्मिकों की सेवा शर्तों में अचानक बदलाव किया जा रहा है, जबकि इन केन्द्रों में कार्य कर रहे अधिकांश कार्मिक लगभग 35 से 40 साल से ज्यादा की सेवाएं दे चुके हैं। कृषि विज्ञान केन्द्रों के राष्ट्रीय फोरम के तत्वाधान में कार्मिकों ने विभिन्न मांगों को लेकर इस हड़ताल का आयोजन किया है। जिसमें सबसे प्रमुख आरएस परौदा समिति की सिफारिशों को लागू करके सभी मेजबान संगठनों के लिए एक केवीके एक नीति (ओकेओपी) को प्रमुखता दी है ताकि इनमें काम करने वाले स भ ी कार्मिक (वैज्ञानिक, तकनीकी, प्रशासनिक और सहायक सहित) समान सुविधाओं का लाभ उठा सके और कृषि विज्ञान केन्द्रों के वेतन भत्तों में कोई असमानता न रहे। इसी परिप्रेक्ष्य में मप्र कृषि विज्ञान केन्द्र इम्प्लॉयज वेलफेयर एसोसिएशन ने भी हड़ताल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर केंद्र के प्रमुख एवं सभी वैज्ञानिक एवं कर्मचारी

कृषि विज्ञान केंद्र बैतूल में एक दिवसीय कलमबंद हड़ताल

इधर, बैतूल में भी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली से शत् प्रतिशत वित्तीय सहायता प्राप्त इस केन्द्र के कार्मिकों के वेतन एवं भत्तों में की जा रही कटौती के विरोध में एक दिवसीय कलम बंद हड़ताल विश्व मृदा स्वास्थ दिवस के अवसर पर 5 दिसम्बर 2024 को की गई। इस हड़ताल का आयोजन कृषि विज्ञान केन्द्रों के राष्ट्रीय संगठन नेशनल फोरम ऑफकेवीके एंड एआईसीआरपी के आह्वान पर संपूर्ण भारत में की गई। गौरतलब है कि देश में लगभग 50 वर्षों से कृषि विज्ञान केन्द्र किसानों के हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन इस केन्द्र के कार्मिकों का विगत चार माह से वेतन भुगतान नहीं हुआ है जिससे कार्मिकों का पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है। उक्त हड़ताल का आयोजन निम्न मांगों को लेकर किया जा रहा है।

- देश भर में केव्हीके के सभी कार्मिकों के लिए वेतन समानता लाना।
- एनपीएस सहित एक समान सेवानिवृत्ति उपरांत के लाभ लागू करना।
- आरएस परौदा उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिषों के अनुसार केव्हीके में समान सेवा शर्तों को लागू करना।
- एसएमएस को वैज्ञानिक/ सहायक प्राध्यापक के रूप में समान रूप से पुनः नामित करना।
- आरएस परोदा उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारी/ स्टॉफपदों का पुनर्गठन।
- उक्त मांगों की ओर आईसीएआर, नई दिल्ली एवं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर के प्रशासिनक अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने हेतु इस एक दिवसीय देषव्यापी हड़ताल संपूर्ण मध्य प्रदेश के कृषि विज्ञान केन्द्रों द्वारा की गई।

फंड के अभाव में चार-चार महीने से मिल मिल रहा वेतन, कैसे हो काम

इधर, देवास में भी कृषि विज्ञान केंद्र देवास के प्रमुख डॉ. एके बड़ाया ने बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र, देवास के समस्त वैज्ञानिक एवं कर्मचारी भी 5 दिसंबर को एक दिवसीय कलमबंद हड़ताल पर रहे। यह सामूहिक कलमबंद हड़ताल पूरे देश के समस्त कृषि विज्ञान केंद्रों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों में शामिल एनपीएस, सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान (ग्रेजुएटी), अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा भत्ता में आईसीएआर एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर द्वारा की गई कटौती के विरोध में की गई है।

इस एक दिवसीय हड़ताल में मध्यप्रदेश के जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर के अधीन कार्यरत कृषि विज्ञान केंद्रों के कमज्चारी संगठन ' केवा ' (कृषि विज्ञान केंद्र एम्प्लोई वेलफेयर एसोसिएशन) के आह्वान पर हड़ताल में शामिल हुए।

केंद्र के समस्त वैज्ञानिक एवं कर्मचारियों की ओर से संगठन द्वारा वरिष्ठ कार्यालय और अधिकारियों को ज्ञापन भेजा गया, जिसमें कृषि विज्ञान केंद्रों में पूर्व में दिए जा रहे समस्त लाभों को समान रूप से लागू रखने एवं सेवानिवृत्ति पश्चात के लाभों को पूर्व की भांति जारी रखने जैसी प्रमुख मांगों को पूरा करने की मांग की गई। डॉ. बड़ाया ने बताया कि फंड के अभाव में कई कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारियों को 4 -5 माह से वेतन का भी भुगतान नहीं हो पा रहा है। देवास केंद्र के कर्मचारियों का भी दो माह से वेतन भुगतान लंबित है।

वेतन भत्तों में कटौती को लेकर नाराज वैज्ञानिकों-कर्मचारियों की हड़ताल

इधर, प्रदेश शिवपुरी में भी कृषि विज्ञान केन्द्र, शिवपुरी के समस्त कर्मचारी 5 दिसम्बर 2024 को एक दिवसीय कलम बंद हड़ताल पर थे। यह सामूहिक कलमबंद हड़ताल पूरे देश के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्रों में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन भत्तों में शामिल एनपीएस, सेवानिवृत्ति सह मृत्यु उपादान (ग्रेजुएटी), अवकाश नगदीकरण, चिकित्सा भत्ता में आईसीएआर द्वारा की गई कटौती को लेकर की जा रही है।

उक्त कटौती को आगामी आदेश तक स्थगन किए जाने के लिए उच्च न्यायालय प्रमुख पीठ जबलपुर द्वारा दिए गए आदेश का पालन न किए जाने पर, माननीय एवं वरिष्ठ अधिकारियों के ध्यानाकर्षण लाने के लिए किया गया

है। कृषि विज्ञान केन्द्रों में पूर्व में दिए जा रहे समस्त लाभों को समान रूप से लागू रखने एवं सेवानिवृत्ति पश्चात के लाभों को पूर्व की भांति जारी रखने जैसी प्रमुख मांगों को लेकर सांकेतिक विरोध किया जा रहा है। किंतु केन्द्र की जीवंत इकाईयों का पूर्ण ध्यान रखा जा रहा है।

मांगों को लेकर संगठन ने उच्च कार्यालय को भेजा ज्ञापन

यह हड़ताल, मप्र. के दोनो जवाहरलाल नेहरू जबलपुर एवं राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय ग्वालियर के अधीन कार्यरत कृषि विज्ञान केन्द्रों के कर्मचारी संगठन (कृषि विज्ञान केन्द्र एम्प्लोई वेलफेयर एसोसिएशन) के तहत मध्यप्रदेश के समस्त कृषि विज्ञान केन्द्रों के समस्त कर्मचारियों द्वारा 05 दिसम्बर 2024 को की गई है। समस्त स्टॉफ की ओर से संगठन द्वारा ज्ञापन भी वरिष्ठ कार्यालय और अधिकारियों की ओर भेजा गया है। उच्च स्तर से भी कृषि विज्ञान केन्द्रों के कर्मचारियों के वेतन भत्तों एवं सेवानिवृत्ति लाभों को पूवज् की भांति निरंतर रखे जाने का अनुरोध किया गया है।

डरावना जीव बन रहा आय का बेहतरीन जरिया

छिपकली पालन से एक रात में 5 हजार तक की कमाई

भोपाल। जागत गांव हमार

अधिकतर घरों में अक्सर छिपकलियां देखने को मिलती हैं। ये भले ही कोई नुकसान नहीं पहुंचातीं हो, लेकिन कई लोगों को असहज जरूर कर देती हैं। ऐसे में ज्यादातार लोग इन्हें घर से भगाने के लिए तरह-तरह के उपाय करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कुछ ऐसे देश भी जहां छिपकलियों को पाला जाता है। यहां हैडलैंप और हाथों में मोटी लकड़ी लेकर रात के वक्त कुछ लोग निकलते हैं और घरों में जाकर छिपकलियां पकड़ते हैं। इससे इन लोगों का घर चलता है और अच्छी खासी कमाई करते हैं।

इन देशों में होता है छिपकली पालन- खासतौर पर थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों में छिपकलियों का पालन बड़े स्तर पर किया जाता है। छिपकली पालन में सबसे अधिक टोकाय गेको नामक प्रजाति की छिपकलियों को पाला जाता है। इस प्रजाति की छिपकलियां औषधीय गुणों के लिए पहचानी जाती है। इन्हें कुछ लोग जंगलों, गांवों और पुराने घरों में जाकर पकड़ते हैं।

कैसे पकड़ते हैं छिपकलियां

छिपकलियां पकड़ने के लिए यहां के लोगों के पास लगभग 2 मीटर लंबी लकड़ी होती है, जिसकी नोक पर गोंद लगा होता है। ये लोग रात के वक्त इस लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। जब छिपकली लकड़ी की नोक से चिपक जाती है, तो उसे सावधानी से हटाकर एक बक्से में डाल देते हैं और एक ही रात में करीब 400 से 450 छिपकलियां पकड़ लेते हैं। इसके अलावा, बारिश के मौसम में छिपकलियों की संख्या बढ़ जाती है, क्योंकि ये जीव मच्छरों का शिकार करने के लिए बढ़ी संख्या में आते हैं। इससे छिपकली पकड़ने वालों के लिए काम और भी आसान हो जाता है। पकड़ी गई छिपकलियों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है और इनके लिए खास तरह का वातावरण तैयार किया जाता है। छिपकलियों को स्वस्थ रखने के लिए सही आहार और देखभाल दी जाती है।

एक रात में पांच हजार की कमाई

छिपकली पालन का बिजनेस इन लोगों के लिए एक अच्छा खासा आय का साधन बन चुका है और इसके जरिए वे अपनी जिंदगी को बेहतर बना रहे हैं। स्थानीय स्तर पर लोग छिपकलियां को पकड़कर एक रात में ही लगभग 2000 से 5000 रुपए तक की कमाई कर लेते हैं। जबकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में एक दुर्लभ छिपकली को बेचने पर 50 हजार से लेकर एक लाख या उससे अधिक की कमाई कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें, टोकाय गेको जैसी दुर्लभ प्रजातियों की छिपकलियां अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारी कीमतों पर बिकती हैं। इस प्रजाती की एक छिपकली की कीमत हजारों से लेकर लाखों तक में हो सकती है।

छिपकलियों का उपयोग

छिपकलियां पारंपरिक चिकित्सा और अन्य उद्योगों में कई महत्वपूर्ण उपयोगों के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। इसके अलावा, चीन की मेडिकल इंडस्ट्री में छिपकलियां का विशेष स्थान है। यहां इनका औषधियों में उपयोग किया जाता है, जो अस्थमा, गठिया और त्वचा रोगों के उपचार में मददगार मानी जाती हैं। इनकी त्वचा और अन्य अंगों का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है, जिससे विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं का इलाज किया जाता है। वहीं, कुछ देशों में छिपकलियों का उपयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है। इन्हें प्रोटीन और अन्य पोषक तत्वों का अच्छा गेत माना जाता है और विभिन्न व्यंजन तैयार किए जाते हैं।

आजीविका मिशन से जुड़कर लखपति दीदी अनुसुईया ने रचे सफलता के नए आयाम

केले के रेशों से बुना सपनों का ताना बाना, लंदन पहुंची बुरहानपुर की टोपी

भोपाल। जागत गांव हमार

मध्यप्रदेश का बुरहानपुर केले की खेती के लिए प्रसिद्ध है, अब अपने नवाचारों के लिए भी जाना जा रहा है। यहां की महिलाओं ने अपने हुनर से न केवल अपने जीवन को संवारा, बल्कि जिले का नाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर रोशन किया है। इन महिलाओं में से एक हैं एकझिरा गांव की अनुसुईया चौहान, जिन्होंने केले के तने के रेशे से टोपी बनाकर लंदन तक अपनी पहचान बनाई है। बुरहानपुर में आयोजित बनाना फेस्टिवल ने अनुसुईया दीदी को नई ऊर्जा और प्रेरणा दी। अनुसुईया दीदी का जीवन बदलने की कहानी आजीविका मिशन से शुरू होती है। लव-कुश स्व-सहायता समूह से जुड़ने के बाद उन्होंने केले की खेती के साथ-साथ केले के तने का भी उपयोग करना शुरू किया। मिशन के सहयोग से उन्होंने रेशा निकालने की मशीन खरीदी और तने से रेशा निकालकर टोपी बनाने का काम शुरू किया। केले के तने से रेशा निकालने, उसे सुखाने और बुनाई करने के बाद विभिन्न आकार और डिज़ाइन की टोपियाँ तैयार की जाती हैं। इन टोपियों की कीमत 1100 से 1200 रुपये तक होती है। अनुसुईया दीदी अपने परिवार के साथ मिलकर यह कार्य करती हैं। इस काम से न केवल उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, बल्कि उन्होंने अन्य महिलाओं को भी प्रेरित किया है।

दीदी ने लंदन में बनाई पहचान

अनुसुईया दीदी द्वारा बनाई गई टोपियां लंदन तक पहुंची हैं। लालबाग क्षेत्र के परिवार के सदस्यों ने यह टोपियां खरीदीं और विदेश तक पहुंचाया। यह कहानी इस बात का प्रमाण है कि यदि सही दिशा और प्रोत्साहन मिले, तो स्थानीय उत्पाद अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी छाप छोड़ सकते हैं।

सरकार के प्रयास और महिलाओं का आत्मनिर्भर सफर

बुरहानपुर जिले में सरकार की मंशा के अनुसार, स्व सहायता समूह की महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का प्रयास जारी है। अनुसुईया दीदी इस सपने को साकार करने वाली मिसाल बन चुकी हैं। उनका कहना है, जब हुनर को सही मंच मिलता है, तो सपने भी साकार होते हैं। आज वे महिलाओं के लिए प्रेरणा स्त्रोत बन गई हैं। उनका सफर इस बात का उदाहरण है कि कैसे नवाचार और मेहनत से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ाए जा सकते हैं।

मटर की फसल में लग गया है रोग?

मटर की फसल में लग गया रोग तो इन तरीकों से उपचार करें किसान

भोपाल। ठंड की शुरुआत के साथ ही फसलों पर भी रोगों और कीटों के प्रकोप की घटनाएं सामने आने लगती हैं। ऐसे में किसानों के लिए फसल की रक्षा के लिए देखभाल और रोगों-कीटों से बचाने के लिए कीटनाशी और रोगनाशी दवाओं का छिड़काव करने की जरूरत होती है। लेकिन, कई बार किसान रोगों की पहचान नहीं कर पाते और उनकी उपज प्रभावित हो जाती है या पूरी तरह चौपट ही हो जाती है, जिससे उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। ऐसे में आज हम आपको मटर की फसलों को लेकर आगाह करने जा रहे हैं। इन दिनों मटर की फसलों में कवकजनित रोगों और कीटों के हमले का खतरा रहता है। कृषि वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट्स ने मटर किसानों के लिए एडवाइजरी जारी की है। कृषि एक्सपर्ट्स ने किसानों को मटर फसल की नियमित निगरानी करने की सलाह देते हुए फसलों में कवकजनित रोगों जैसे-रतुआ तथा चूर्णिल आसिता की रोकथाम के लिए रोगनाशक दवाओं के छिड़काव की सलाह दी है।

चूर्णिल आसिता रोग के लिए छिड़कें ये दवा

कृषि एक्सपर्ट के अनुसार, सल्फरयुक्त कवकनाशी सल्फेक्स को 2.5 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर के हिसाब से 800-1000 लीटर पानी में घोलकर 15 दिनों के अंतराल पर 2-3 बार फसल पर जरूरत के हिसाब से छिड़काव करें या घुलनशील गंधक (0.2.0.3 प्रतिशत) का फसल पर छिड़काव करें। वहीं, चूर्णिल आसिता को कंट्रोल करने के लिए कार्बेन्डाजिम (1 ग्राम/लीटर पानी) या डीनोकैप, केराथेन 48 ई.सी. (0.5 मि.ली./लीटर पानी) का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

रतुआ रोग को ऐसे करें दूर

रतुआ रोग की रोकथाम के लिए मैन्कोजेब दवा की 2.0 कि.ग्रा. या डाइथेन एम-45 को 2 कि.ग्रा. प्रति हेक्टेयर या हेक्साकोनाजोटा 1 लीटर या प्रोपीकोना 1 लीटर की दर से 600-800 लीटर पानी में घोलकर खड़ी फसल पर छिड़काव करें। कृषि एक्सपर्ट ने सलाह दी है कि किसान उचित फसलचक्र अपनाएं और रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें।

तनाछेदक-फलीछेदक की ऐसे करें रोकथाम

इंडोक्साकार्ब (1 मिली प्रति लीटर पानी) का छिड़काव कीटों से होने वाले नुकसान को कम करता है। मटर के तनाछेदक कीट की रोकथाम के लिए डाइमिथोएट 30 ईसी दवा को 1.0 लीटर मात्रा और फलीछेदक कीट की रोकथाम हेतु मोनोक्रोटोफॉस 36 ई.सी. दवा की 750 मिली की दर से 800 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करें। मटर की खेती करना किसानों के लिए काफी फायदेमंद हो सकता है, क्योंकि इससे मिट्टी की उपजाऊता भी बढ़ती है।

जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

विश्वविद्यालय ने 51 एग्री स्टार्टअप्स को दी नई उड़ान, लोगो का किया विमोचन

स्टार्टअप्स को मिलता है 25 लाख रुपए तक का अनुदान, आनलाइन जारी होती है राशि

जबलपुर। जागत गांव हमार

कृषि क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय (जेएनकेवीवी), जबलपुर ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्वविद्यालय ने 51 एग्री स्टार्टअप्स को सफलतापूर्वक स्थापित किया और इनके मोनो (लोगो) का विमोचन किया। यह आयोजन कृषि व्यवसाय प्रबंधन संस्थान (आईएबीएम) में चल रहे 30 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हुआ।

जे-राबी: एग्री उद्यमिता की अनूठी पहल

जे-राबी (जनाहर राबी) कार्यक्रम की शुरुआत जेएनकेवीवी में वर्ष 2018-19 में हुई थी। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है। जे-राबी मध्य प्रदेश में स्थित एकमात्र एग्री बिजनेस इनक्यूबेटर है, जो ग्रामीण उद्यमिता पर केंद्रित है। अब तक इस कार्यक्रम ने राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशेष पहचान बनाई है।

2027 तक 1000 करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य

जे-राबी की एक छोटी, लेकिन समर्पित 7-8 सदस्यों की टीम ने इन वर्षों में उल्लेखनीय कार्य करते हुए 51 कंपनियों को स्थापित किया है। इन कंपनियों का वार्षिक टर्नओवर 2023-24 में 166 करोड़ था, जो चालू वित्तीय वर्ष के प्रथम छः महीनों में 126 करोड़ तक पहुंच गया। संस्था ने वर्ष 2027 तक 1000 करोड़ के टर्नओवर का लक्ष्य रखा है। जे-राबी ने 6वें बैच के लिए कुल 149 आवेदनों में से 41 अभ्यर्थियों का चयन किया है। इन 41 प्रतिभागियों को 30 दिनों तक गहन प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसमें व्यापार प्रबंधन, वित्तीय योजना, ब्रांडिंग, विपणन और उत्पादन रणनीतियों जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने मार्गदर्शन दिया। इस कार्यक्रम के अंतिम चरण में प्रतिभागियों को अपनी योजनाओं पर प्रस्तुति देनी होगी, ताकि वे उच्चस्तरीय चयन समिति के सामने अपने प्रोजेक्ट्स को प्रस्तुत करने के लिए तैयार हो सकें।

स्टार्टअप्स के लिए अनुदान श्रेणियां

स्टार्टअप्स को तीन श्रेणियों में अनुदान प्रदान किया जाता है। छात्रों के स्टार्टअप्स को चार लाख रुपये तक, प्रेरणा श्रेणी के स्टार्टअप्स को पांच लाख रुपये तक और साकार श्रेणी के स्टार्टअप्स को 25 लाख रुपये तक का अनुदान मिलता है। अनुदान प्राप्त करने के लिए स्टार्टअप्स को कंपनी का पंजीकरण अनिवार्य रूप से पूरा करना होता है। चयनित स्टार्टअप्स और जे-राबी के बीच एक अनुबंध किया जाता है, जिसके बाद टीम उनके परिसर में जाकर सत्यापन करती है। सत्यापन पूरा होने के बाद अनुदान की राशि ऑनलाइन स्थानांतरित की जाती है।

स्थानीय से राष्ट्रीय पहचान तक का सफर

जे-राबी का कार्यक्षेत्र पहले राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक जैसे राज्यों तक फैला हुआ था। इस वर्ष जम्मू-कश्मीर से केरल और गुजरात से पश्चिम बंगाल तक के ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए। हालांकि, इस साल से कार्यक्षेत्र को मध्य प्रदेश तक सीमित कर दिया गया है। पिछले वर्ष, 26 में से 18 स्टार्टअप्स को अनुदान मिला। इस बार चयन प्रक्रिया को और पारदर्शी बनाने के लिए 41 स्टार्टअप्स का पंजीकरण पहले ही पूरा कर लिया गया है। टीम का लक्ष्य है कि 2024-25 में 41 में से 24 स्टार्टअप्स को अनुदान दिलाया जाए। कार्यक्रम में कुलपति प्रो. पी.के. मिश्रा, आईएबीएम के निदेशक डॉ. मोनी थॉमस, डॉ. लगीना शर्मा, लक्ष्मी सिंह, डॉ. दीपक पाल, दीपांशु पटेल और बड़ी संख्या में स्टार्टअप्स से जुड़े प्रतिनिधि मौजूद रहे। इस अवसर पर प्रतिभागियों ने अपने अनुभव साझा किए और जे-राबी की भूमिका की सराहना की।

जागत गांव हमार, सलाहकार मंडल

1. प्रो. डा. केआर मौर्य, पूर्व कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसासमस्तीपुर (बिहार) एवं महात्मा ज्योतिराव फूले विश्वविद्यालय, जयपुर (राजस्थान) ईमेल-kuber.ram@gmail.com, मोबा- 7985680406

2. प्रो. डा. गैब्रियल लाल, प्रोफेसर, आनुवांशिकी एवं पादप प्रजनन विभाग सैम हिंगिन बॉटम यूनिवर्सिटी आफएग्रीकल्चर, टेक्नालोजी एंड साइंसेज, प्रयागराज, उप्र। ईमेल- द्दड्डद्बड्ढ्डiyal.lal @shiats.edu.in, मोबा- 7052657380

3. डा. वीरेन्द्र कुमार, प्रोफेसर एंड हेड, पौध रोग विज्ञान विभाग, डा. राजेन्द्र प्रसाद केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय परिसर ढोली, मुजफ्फरपुर बिहार। ईमेल- birendraray@gmail.com मोबा- 8210231304

4. डा. नरेश चन्द्र गुप्ता, वैज्ञानिक, मृदा विज्ञान, कृषि महाविद्यालय बिरसा, बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कॉके, रॉची झारखण्ड। ईमेल- ncgupt-abau@gmail.com, मोबा- 8789708210

5. डा. देवेंद्र पाटिल, वैज्ञानिक (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, सीहोर (मध्यप्रदेश) सेवनिया, इछावर, सिहोर (मप्र) ईमेल- dpatil889@gmail.com, मोबा- 8827176184

6. डा. आशुतोष कुमार सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, एग्री विजनेस मैनेजमेंटकृषि अर्थशास्त्र विभाग, एकेएस,विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- kumar.ashu777@gmail.com, मोबा- 8840014901

7. डा. बिनीता सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर आनुवांशिकी एवं पौध प्रजनन विभाग एकेएस विश्वविद्यालय, सतना, मप्र ईमेल- singhvineeta123@gmail.com, मोबा- 8840028144

8. डा. आरके शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, परिजीवी विज्ञान विभाग, बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना, बिहार। ईमेल- drrksharmabvc@gmail.com, मोबा- 9430202793

9. डा. दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक, मृदा एवं जल संरक्षण अभियंत्रिकी विभाग, गोविन्द बल्लभ पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, पन्तनगर, उत्तराखण्ड। ईमेल- deepak.swce.cot.gbpuat@gmail.com, मोबा- 7817889836

10. डा. भारती उपाध्याय, विषय वस्तु विशेषज्ञ (शस्य विज्ञान) कृषि विज्ञान केन्द्र, विरौली, समस्तीपुर, बिहार। ईमेल-bharati.upadhya@rpcau.ac.in, मोबा- 8473947670

11. रोमा वर्मा, सब्जी विज्ञान विभाग महात्मा गांधी उद्यानिकी एवं् वानिकी विश्वविद्यालय, पाटन, जिला- दुर्ग, छत्तीसगढ़। ईमेल- romaverma35371@gmail.com, मोबा- 6267535371

कृषि में जलवायु परिवर्तन से निपटने आरडीए योजना

नई दिल्ली। जलवायु परिवर्तन कृषकों के लिए एक बड़ी चुनौती है। सरकार ने 2008 में जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) की स्थापना की। यह देश में जलवायु परिवर्तन पर उपायों के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा प्रदान करती है। एनएपीसीसी देश को जलवायु परिवर्तन के अनुकूल बनाने और पारिस्थितिक स्थिरता को बढ़ाने में सक्षम बनाने के लिए एक राष्ट्रीय नीति की रूपरेखा तैयार करती है। एनएपीसीसी के अंतर्गत राष्ट्रीय मिशनों में से एक राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (एनएमएसए) है। यह बदलती जलवायु के लिए कृषि को अधिक अनुकूल बनाने के लिए नीतियों को विकसित और कार्यान्वित करता है। कृषि में जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौती को ध्यान में रखते हुए देश भर में कृषि क्षेत्र में प्रतिकूल जलवायु स्थितियों से निपटने के लिए सरकार द्वारा एनएमएसए के अंतर्गत कई योजनाएं शुरू की गई हैं। सूक्ष्म सिंचाई प्रौद्योगिकियों यानी बूंद-बूंद और फव्वारा सिंचाई प्रणालियों के माध्यम से खेतों में जल उपयोग की दक्षता को बढ़ाने के लिए 2015-16 के दौरान प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी) योजना शुरू की गई थी।

जागत गांव हमार के सुधि पाठकों...

» जागत गांव हमार कृषि, पंचायत और ग्रामीण विकास आधारित समाचार पत्र है, जिसके लिए आपका स्नेह और प्यार हमें शुरू से मिलता रहा है। हम आशा और विश्वास करते हैं कि आगे भी मिलता रहेगा।

» समाचार पत्र के लिए विशेषज्ञों की राय, प्रकाशन योग्य सामग्री के साथ-साथ आपके समक्ष इसे पहुंचाने तक हमारी जिम्मेदारी बड़ी चुनौतीपूर्ण है। आपके सहयोग से ही हम इस चुनौती का सामना कर पाएंगे।

» ऐसे में हमारी आपसे अपेक्षा और आग्रह है कि जागत गांव हमार के वार्षिक सदस्य बनें और इसके लिए नीचे लिखे गए नंबर पर संपर्क करें।

संपर्क करें- अजय द्विवेदी-9229497393, 94250485889

"आपका सहयोग हमारी मजबूती का आधार बनेगा"

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं एमआईजी 30, शिवकल्प, अयोध्या बाईपास भोपाल, मप्र से प्रकाशित। संपादकः अजय कुमार द्विवेदी, स्थानीय संपादकः- अरविंद मिश्रा, **संपर्क** -9229497393, 9425048589, ईमेलः- jagatgaon.bpl@gmail.com (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)